© 2017 IJSRST | Volume 3 | Issue 7 | Print ISSN: 2395-6011 | Online ISSN: 2395-602X
Themed Section: Science and Technology

पूर्वी उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक कृषि की स्थिति एवं संभावनाएँ

बृजमोहन सिंह यादव
शोधछात्र
भूगोल विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

भारत आज भी एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश है। क्योंकि यहाँ 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या कृषि एवं इससे जुड़े कार्यों में लगी हुई है अतः कृषि एवं कृषकों का विकास किये बिना भारतीय अर्थव्यवस्था को समृद्ध नहीं किया जा सकता। इसी बात के महत्व को समझते हुए भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2022 तक कृषकों की आय को बढ़ाकर दोगुना करने का लक्ष्य रखा एवं इसकों प्राप्त करने के लिए 7 बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देने की बात कही जिसमें एक प्रमुख प्रयास था व्यावसायिक कृषि का विकास एवं विस्तार।[1] जिसके अर्न्तगत मुख्य रूप से पशुपालन मछली पालन, पोस्टहार्वेस्ट सुविधाओं में सुधार व नकदी फसलों के उत्पादन पर विशेष ध्यान देने का लक्ष्य रखा गया ताकि 2022 तक कृषकों की दोगुनी आय के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। व्यावसायिक कृषि कि दृष्टि से उ0प्र0 में भी व्यापक सम्भवनाऐं है। उत्तर प्रदेश भारत के अग्रणीय राज्यों में से एक है, उपजाउ जलोढ़ मैदान उपयुक्त कृषि जलवायु के कारण यहाँ कृषि क्रियाओं का पर्याप्त विकास हुआ परन्तु 'व्यावसायिक कृषि (जिसके अन्तर्गत कृषक अत्यधिक लाभ हेतु फल–फूल, सब्जियाँ, मसालें एवं अन्य नकदी फसलों के उत्पादन के साथ–साथ पशुपालन करते है।) का विकास प्रदेश की क्षमताओं के अनुसार नहीं हो पाया है। विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो व्यावसायिक कृषि की स्थिति और भी दयनीय है, जहाँ कुल कृषित भूमि के मात्र 10.52 प्रतिशत भागपर ही व्यावसायिक कृषि की जाती है, जबकि प्रदेश स्तर पर इसका प्रतिशत 22.46 तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो 34 प्रतिशत है।[2] साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में इनकी उत्पादकता भी उपरोक्त की अपेक्षा कम है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश जिसका विस्तार 85.84 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में है। मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के चार कृषि जलवायु प्रदेशों, उत्तर–पूर्वी मैदान, मध्य मैदान, विध्यन प्रदेश तथा पूर्वी मैदान के 27 जिलों में विस्तृत है, जहाँ औसतन 120 से0मी0 की वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है एवं अधिकांश भूभाग पर उपजाऊ जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है, आर्थिक दृष्टि से कृषि इस क्षेत्र का प्रमुख व्यवसायिक आधार है।

व्यावसायिक कृषि के तहत पूर्वी उत्तर प्रदेश में बांगवानी (हार्टीकल्चर) के अन्तर्गत मुख्य रूप से सब्जियों, फल, मसाले, जैविक खेती वाली फसलों एवं अन्य औषधीय फसलों का उत्पादन किया जाता है, जिसमें प्रदेश स्तर पर 8.3 प्रतिशत की अच्छी वृद्धि दर पायी गयी जिसे 2017–18 के अन्त तक 10.4 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य है।[3] पशुपालन के क्षेत्र में यहाँ दुग्ध व्यवसाय का अपेक्षाकृत अधिक विकास हुआ है। जिसमें अधिकतर किसान कृषि के साथ–साथ पशुपालन भी करते हैं एवं दुग्ध उत्पादन कर स्थानीय जिला मुख्यालयों एवं शहरों में बेचते है। गांवों में डेरी फार्मों का विकास शहरों की अपेक्षा कम है जबकि शहरों में बड़े–बड़े फार्मों में बड़ी मात्रा में दुधारू गायों एवं भैसों को रखकर संयोजित दुग्ध व्यवसायों का विकास किया गया है।[5] दुग्ध व्यवसाय के अलावा यहाँ मांस हेतु भैंस, बकरी, भेड़ सुअर इत्यादि का भी सीमित मात्रा में पालन किया जाता है। चूंकि क्षेत्र के अधिकांश किसान सीमांत या लघु कृषक हैं जिनके पास तकनीकी, पूँजी एवं कृषि ज्ञान का अभाव है। अतः ये कृषि के सर्वोत्तम लाभ से वंचित रह जाते हैं। फिर भी जिन क्षेत्रों विशेषकर शहर के निकटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ उपयुक्त कृषि बाजार, पोस्टहार्वेस्ट, सुविधाएँ एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध है वहां कृषि का तेजी से विकास हुआ है। विशेषकर छोटी जोत के किसानों ने अत्यधिक लाभ हेतु खाद्यान्न फसलों गेहूँ, जौ, बाजरा, धान की आपेक्षा नकदी फसलों जैसे सब्जी, फल–फूल, मसालें इत्यादि के उत्पादन पर ध्यान दिया है ताकि अत्यधिक लाभ प्राप्त किया जा सके।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में औद्योगिक ईकाइयों, सुक्ष्म एवं लघु उद्योगों के अभाव, उच्च जनसंख्या भार, सीमांत व लघु कृषि जोत, कमजोर आधारभूत संरचना के कारण क्षेत्र के अधिकांश कृषक गहन निर्वाह कृषि को अपनाए हुए है। 1960 के बाद हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति के द्वारा कृषि व्यवस्था में सुधार के प्रयास किये गये, जो उत्तर पश्चिमी भारत तथा खाद्यान्न फसलों विशेषकर गेहूँ–धान एवं मक्का के उत्पादन तक सीमित रहे तथा व्यवसायिक कृषि का विकास अपेक्षाकृत कम हो सका।[4] पुनः आर्थिक सुधारों के दूसरे दौर 1990 के दशक तथा 21वीं सदी के शुरूआत में इस हेतु प्रयास किये गये और सुधार भी हुए परन्तु प्रदेश का यह पूर्वी भाग पश्चिमी भाग की अपेक्षा फिर व्यावसायिक कृषि के विकास में पीछे रह गया।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक कृषि का क्षेत्र एवं उत्पादक्ता दोनों अत्यंत सीमित है, अभी भी यहाँ व्यावसायिक कृषि मुख्यधारा में नहीं शामिल हो पायी है। क्षेत्र में सदाबहार क्रांति (Evergreen Revolution) हेतु व्यावसायिक कृषि क्रियाओं के विकास की अपार संभावनाएँ है। परन्तु इस हेतु व्यापक स्तर पर कृषि विकास सुविधाओं में सुधार एवं कृषि जागरूकता लानी होगी, ताकि क्षेत्र के ग्रामीणों एवं कृषकों हेतु अन्य रोजगार साधन उत्पन्न कर इनके आर्थिक स्थिति एवं जीवन स्तर में सुधार किया जा सके।

आज भी 21वीं शताब्दी जिसे तकनीकि शताब्दी का युग कहा जाता है, भारतीय कृषि विशेष कर पूर्वी उत्तर प्रदेश में कृषि तकनीकि का पर्याप्त विकास नहीं होने से इन क्षेत्रों में कृषि विशेषकर व्यावसायिक कृषि का विस्तार इनकी क्षमताओं के अनुरूप नहीं हो पाया है, जिसमें प्रमुख बाधाएँ कमजोर आधारभूत संरचना, कृषि एवं कृषि तकनीकि अशिक्षा एवं स्वस्थ व लाभाकारी वित्त व बीमा सुविधाओं की अल्प उपलब्धता रही है। योजना आयोग उत्तर प्रदेश ने 12वीं पंचवर्षीय योजना रिपोर्ट में दर्शाया है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में विशेषकर सीमांत एवं लघु कृषकों को व्यवसायिक कृषि की ओर रूपानान्तरित कर कृषकों की आय में त्वरित वृद्धि की जा सकती है। 2014–15 के राज्य कृषि नीति उत्तर प्रदेश में इसी को ध्यान में रखकर कृषि को लाभकारी बनाने हेतु विशेषकर पोस्टहार्वेस्ट सुविधाओं जैसे खाद्य प्रसंस्करण, अनुकूल कृषि बाजार इत्यादि के विकास पर जोर दिया गया।[6] ताकि राज्य में व्यावसायिक कृषि का व्यापक रूप से विस्तार कर कृषकों एवं ग्रामीणों की प्रमुख समस्याओं जैसे प्रछन्न बेरोजगारी, गरीबी एवं निम्न जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके एवं कृषि को एक आर्कषक व्यवसाय बनाया जा सके एवं 2022 तक कृषकों की आय को दोगुना करने के नीति आयोग के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके क्योंकि भारतीय कृषकों एवं ग्रामीणों का विकास किये बिना भारत एवं भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास संभव नहीं है।

संदर्भ

1. DOUBLING FARMER'S INCOME (Rationale, Strategy, Prospects and Action Plan) Ramesh Chand, National Institution for Transforming India (NITI) Government of India, New Delhi, March 2017.
2. Planning Atlas, Uttar Pradesh, 2013-14 Planning commission of Uttar Pradesh.
3. 12th Five Year Plan and Annual Plan 2012-13, Volume-I (P-II) Planning commission of Uttar Pradesh.
4. Annual Report 2016-17, Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries, Ministry of Agriculture and Farmers welfare, Govt. of India.
5. M.S. Swaminathan : Combating Hunger and Achieving Food Security, Combridge University Press, Page No.-7.
6. राज्य कृषि नीति उत्तर प्रदेश 2013, कृषि विभाग उत्तर प्रदेश।